

असम	85.89%
केरल	78.27%
पुडुचेरी	89.87%



गुवाहाटी/तिरुवनंतपुरम/पुडुचेरी। देश के दो राज्यों असम, केरलम, केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए। 1950 में असम के बनने के बाद से राज्य में सबसे ज्यादा 85.89 फीसदी वोटिंग हुई। इससे पहले 2016 में 84.7 फीसदी मतदान हुआ था। पुडुचेरी में आजादी के बाद सबसे ज्यादा 89.87 फीसदी मतदान हुआ। इससे पहले का रिकॉर्ड 85 फीसदी (2006, 2011 और 2016 विधानसभा चुनाव) का था। केरलम में पिछले 49 सालों में दूसरी सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, यहाँ 78.27 फीसदी वोट डाले गए। 1977 में रिकॉर्ड 79.2 फीसदी मतदान हुआ था। वोटिंग परसेंट के आंकड़े 9 अप्रैल की रात 11.30 बजे तक के हैं। चुनाव आयोग का फाइनल आंकड़े जारी करना बाकी है। असम में 126 सीटों पर 722 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला होगा। 35 जिलों में से 26 से ज्यादा जिलों में 80 फीसदी से ऊपर वोटिंग हुई। केरलम में 140 सीटों पर 883 उम्मीदवार मैदान में थे। 14 जिले में से दो जिलों में 80 फीसदी से ऊपर मतदान हुआ। पुडुचेरी की 30 सीटों में कुल 10 लाख मतदाता हैं। यहाँ दो जिले हैं। सबसे ज्यादा 90.47 फीसदी मतदान पुडुचेरी जिले में हुआ। वहीं करईकल में 86.77 वोटिंग हुई।



अगले माह से गांव में भी मुफ्त नहीं मिलेगा पानी!

प्रदेश में 23 हजार से अधिक पंचायतें

मुख्य संवाददाता, भोपाल। प्रदेश की 23 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में अब पीने के पानी की सप्लाई और पाइपलाइन के रखरखाव की जिम्मेदारी पूरी तरह से ग्राम पंचायतों के हवाले होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए नए नियम तैयार कर लिए हैं। इसके तहत अब हर गांव में एक पानी समिति बनाई जाएगी। यह समिति न केवल नल कनेक्शन दिलाएगी, बल्कि यह भी तय करेगी कि गांव के लोगों के लिए वाटर टैंक्स की दरें कतनी तय की जाएं। खास बात यह है कि अगर कोई उपभोक्ता लगातार तीन महीने तक पानी का बिल नहीं भरेगा, तो पंचायत उसका नल कनेक्शन काट सकेगी। इसके अलावा पानी की बर्बादी करने वालों पर भी नकेल कसी गई है।

पाइपलाइन से पानी फैलाते पाए जाने पर 100 से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। ग्राम पंचायतें अब वाटर टैंक्स की राशि से ही बिजली बिल के साथ अन्य खर्च भी करेगी। सरकार ने इन नियमों में ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया है कि वे गांव के 5 से 10 ऐसे परिवारों का पानी का बिल माफ कर सकती हैं, जो बेहद गरीब हैं या जिनमें कोई दिव्यांग या विधवा महिला है। नल-जल योजना चलाने के लिए पंचायतों को एक पंप ऑपरेटर रखने की भी छूट दी गई है, जिसका वेतन वसूले गए वाटर टैंक्स की रकम से दिया जा सकेगा। पानी की शुद्धता को लेकर भी सख्ती बरती गई है। अब पंचायतों को समय-समय पर फील्ड टेस्ट किट के जरिए पानी की जांच करनी होगी और उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर डालनी होगी। यदि पानी पीने लायक नहीं पाया गया, तो सप्लाई तुरंत रोककर उसकी लैब में जांच करानी होगी।



100-500

रुपए तक हर माह देना होगा पानी के लिए टैक्स

03

माह बिल न भरने पर कटेगा कनेक्शन

हर माह जलकर न्यूनतम रेट किए तय

प्रकार	दर (रुपए प्रतिमाह में)
● घरेलू कनेक्शन (ट्राइबल ब्लॉक)	60
● घरेलू कनेक्शन (मास्टर प्लान एरिया)	120
● घरेलू कनेक्शन (सामान्य पंचायत)	100
● स्कूल, कॉलेज जैसी सार्वजनिक संस्था	200
● इंडस्ट्रीज	उपयोग की मात्रा पर
● गैर घरेलू (इंडस्ट्री से अलग)	500

कनेक्शन चार्ज

● एससी/एसटी परिवार	1000
● अन्य परिवार	2500
● सार्वजनिक संस्था	5000
● इंडस्ट्री	10000
● गैर घरेलू (इंडस्ट्री से अलग)	8000

अब पंचायत को तत्काल सुधारना होगा लीकेज

नई व्यवस्था में शिकायतों के निपटारे के लिए भी समय-सीमा तय कर दी गई है। यदि किसी ग्रामीण के नल में तकनीकी खराबी आती है, तो पंचायत को उसे दो से तीन दिन के भीतर ठीक करना होगा। ग्रामीण अपनी शिकायतें सीधे पंचायत कार्यालय या सीएम हेल्पलाइन पर भी दर्ज करा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से गांवों में पानी की बर्बादी रुकेगी और लोगों को नियमित रूप से शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। साथ ही, बिजली बिलों के भुगतान और छोटी-मोटी मरम्मत के लिए अब पंचायतों को सरकार का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, क्योंकि वे जल कर से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल इन कामों में कर सकेंगे।

सूबे में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 26 आईएस के तबादले 14 जिलों के कलेक्टर बदले प्रियंक को भोपाल की कमान

विशेष संवाददाता, भोपाल। राज्य सरकार ने गुरुवार देर शाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 26 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें भोपाल सहित 14 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है, जबकि धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा भोपाल के नए कलेक्टर होंगे। पांच जिलों के कलेक्टरों को फिर से दूसरे जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रशासनिक फेरबदल की बहुप्रतीक्षित सूची सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गुरुवार को देर शाम जारी कर दी गई, जिसमें 14 जिलों के कलेक्टर व एक संभागयुक्त को बदल दिया गया। फेरबदल में रीवा कलेक्टर प्रतिमा पाल को सागर, बैतुल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को रीवा, धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को भोपाल, मंडला कलेक्टर सोमेश मिश्रा को नर्मदापुरम, कलेक्टर श्योपुर अर्पित वर्मा को कलेक्टर शिवपुरी और झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना को सिवनी कलेक्टर बनाया गया है। इन सभी अधिकारियों पर राज्य सरकार ने भरोसा जताते हुए उन्हें लगातार दूसरे जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी तरह सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2014 और 2015 बैच के कई अधिकारियों को उनके बेहतर कार्यप्रणाली के चलते जिलों की कमान सौंपी है। इस सूची में जिन जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, उनमें से कई का कार्यकाल एक ही जिले में दो से तीन वर्ष पूरा हो चुका था। इनमें धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और रीवा कलेक्टर प्रतिमा पाल शामिल हैं।

पहली बार मिली जिलों की जिम्मेदारी

इस फेरबदल में महिला आईएएस अधिकारियों को भी महत्व दिया गया है। इनमें से कई को पहली बार जिले का कलेक्टर बनाया गया है। इनमें हाउसिंग बोर्ड और फिर पर्यटन बोर्ड में बेहतर परिणाम देने की वजह से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की उपसचिव विदिशा मुखर्जी को पहली बार जिले की कमान सौंपी गई है, उन्हें नए जिले मैहर का कलेक्टर बनाया गया है। वहां की कलेक्टर रही रानी बाटड को सहकारिता विभाग में उपसचिव बनाया गया है। लोक सेवा आयोग इंदौर की सचिव राखी सहाय को उमरिया कलेक्टर, सहकारिता विभाग की उपसचिव शीला दाहिमा को श्योपुर और नगर निगम रीवा के आयुक्त डॉ. सीरभ संजय सोनवणे को बैतुल जिले का कलेक्टर बनाया गया है। ये सभी आईएएस अधिकारी पहली बार जिलों की कमान संभालेंगे।



प्रियंक मिश्रा

प्रतिमा पाल

कौशलेंद्र विक्रम

नर्मदापुरम के आयुक्त और कलेक्टर बदले: प्रशासनिक सर्जरी में नर्मदापुरम के संभागयुक्त कृष्णगोपाल तिवारी और वहां की कलेक्टर सोनिया मीना को भी बदला गया है। कमिश्नर तिवारी को आयुक्त सामाजित न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण और कलेक्टर मीना को वित्त विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। **तीन घंटे सीएम, सीएस ने की मंत्रणा:** इससे पहले गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन भवन पहुँचकर मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ तबादलों को लेकर मंत्रणा की। दोनों अधिकारी यहाँ लगभग साढ़े तीन घंटे से ज्यादा समय रहे और स्थानांतरण की सूची को अंतिम रूप दिया। हालांकि, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्षों के नामों को लेकर भी सीएम, सीएस के बीच चर्चा हुई है, लेकिन उन नामों पर अंतिम फैसला नहीं हो सका, जिसके बाद सचिव, अवसर सचिव और उपसचिव स्तर के 26 अधिकारियों के दायित्व बदले जाने का आदेश जारी कर दिया गया। **जनगणना शुरू होने से पहले फेरबदल:** मध्यप्रदेश में जनगणना का कार्य 16 अप्रैल से प्रारम्भ होना है। केंद्र सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर राज्य सरकार से अपेक्षा की थी कि जनगणना के कार्य में लगे अधिकारियों को तय समय तक स्थानांतरित नहीं किया जाए। हालांकि, इसमें आईएएस अधिकारियों को इस दायरे से बाहर रखे जाने की बात कही जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने जनगणना शुरू होने से पहले ही आईएएस अधिकारियों को स्थानांतरित करने का आदेश जारी कर दिया।

सिवनी की कलेक्टर रही शीतला पटेल को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सचिव बनाया गया है। *(तबादला सूची पेज-2 पर)*

MARUTI SUZUKI ARENA

GOT IT ALL.
AND A LOW RATE OF INTEREST.

AVAIL LOAN
@ 3.99%#



VICTORIS

5 STAR SAFETY RATING

BHARAT NCAP



LEVEL 2 ADAS WITH 10+ FEATURES



DOLBY ATMOS SPATIAL SOUND EXPERIENCE



SMART POWERED TAILGATE WITH GESTURE CONTROL



AVAILABLE IN STRONG HYBRID



SCAN AND CONNECT TO
A SHOWROOM NEAR YOU



E-BOOK TODAY AT
WWW.MARUTISUZUKI.COM



CONTACT US AT **1800-102-1800**

Applicable T&C available at your nearest dealership. Creative visualization. Car colour may vary due to printing on paper. Images used are for illustration purposes only. ADAS features are for driver assistance only. Driver is responsible for safe and attentive driving. Features may vary by model/conditions. For details on functioning of safety features according to conditions of usage, please refer to the Owner's Manual. Trademarks/logos being displayed belong to the respective owners. Infiniti is the trademark of HARMAN International Industries, Incorporated. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. *Scheme valid for limited period. Finance at the sole discretion of the financier and may vary based on customer profile. Special Rate of Interest may vary basis subvention amount and customer credit evaluation by the financier. Customer may choose to avail either special rate of interest or applicable customer offers. Offers & price may vary as per model/variant. Limited period offer by select financiers.

VICTORIS





» वर्ष 69 » अंक 191 » पृष्ठ 12
भोपाल, शुक्रवार 10 अप्रैल, 2026
» वैशाख कृष्ण पक्ष 08, विक्रम संवत् 2083
» महानगर » मूल्य 5 रुपए

दैनिक जागरण

www.dainikjagranmpcg.com



अच्छे लोग, अच्छी
किताबें तुरंत समझ में
नहीं आती, उन्हें पढ़ना
पड़ता है।

-अज्ञात

संक्षिप्त खबरें

आज से टोल पर कैश नहीं, सिर्फ यूपीआई

नई दिल्ली, जेएनएन। अगर आप भी नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस वे पर सफर करते हैं, तो खबर आपके लिए है। अब टोल पर सिर्फ ऑनलाइन ही भुगतान करना होगा। केंद्र की ओर से 10 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसके तहत कैश के जरिए टोल टैक्स का भुगतान नहीं किया जा सकेगा। अब सिर्फ यूपीआई या फास्टेग के जरिए ही टोल प्लाजा पर भुगतान किया जाएगा। अगर फास्टेग की जगह यूपीआई से टोल टैक्स का भुगतान करते हैं तो ज्यादा कीमत देनी होगी। अब फास्टेग से 100 रुपए की जगह यूपीआई से 125 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा।

एअर इंडिया फ्लाइट का इंजन बंद, हादसा टला

मुंबई, जेएनएन। मुंबई से बेंगलुरु जा रही एअर इंडिया की एअरबस ए320 एनईओ फ्लाइट एआई 2812 गुरुवार को उड़ान भरने के करीब 20 मिनट बाद वापस मुंबई एयरपोर्ट लौटी। अधिकारियों ने बताया कि हवा में एक इंजन बंद होने पर पायलट ने रेडियो पर 'पैन-पैन' कॉल दी, जिसके बाद फ्लाइट को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित लैंड कराया गया। विमानन इमरजेंसी प्रोटोकॉल में यह कॉल 'मेडे' से एक स्तर नीचे मानी जाती है। इसका मतलब स्थिति गंभीर है और तुरंत सहायता की जरूरत है, लेकिन तत्काल जानलेवा खतरे की स्थिति नहीं है। टेकऑफ के दौरान तेज आवाज सुनाई दी और चिंगारी भी दिखीं। फ्लाइट को सुबह 2.05 बजे उड़ान भरनी थी लेकिन यह करीब 2.30 बजे रवाना हुई थी।

आईपीएल में आज
राजस्थान बनाम बेंगलुरु
समय : शाम 7.30 बजे से
प्रसारण: स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर
परिणाम: लखनऊ ने कोलकाता को 3 विकेट से हराया।

होर्मुज स्ट्रेट से रोजाना गुजरेंगे सिर्फ 15 जहाज

ईरान बोला-प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर होगी सैन्य कार्रवाई

तेहरान, जेएनएन। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से एक दिन में सिर्फ 15 जहाजों को गुजरने की अनुमति दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि यह मंजूरी सिर्फ अमेरिका के साथ जारी अस्थायी संघर्ष विराम के दौरान ही लागू रहेगी। हालांकि, इस दौरान गुजरने वाले जहाजों को ईरान के बनाए सख्त प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। इस प्रोटोकॉल को न मानने वाले जहाजों के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इजरायली हमलों के बाद से ही होर्मुज बंद है। इस कारण पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। रूसी समाचार एजेंसी तास से बात करते हुए एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बताया कि हर बार जहाज के गुजरने के लिए ईरान की मंजूरी, प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। इसके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी होंगी।



भारत भी अंडमान के समंदर में वसूले टोल : बग्गा

नई दिल्ली, जेएनएन। होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजर रहे जहाजों से टोल वसूलने पर ईरान आमदा है। ईरान ने सीजफावर की शर्तों में भी इस बात को रखा है कि वो होर्मुज पर कंट्रोल चाहता है और वहां से होकर गुजर रहे जहाजों से कम से कम एक डॉलर प्रति बैरल का टोल वसूलेगा। इस बीच भारत के डिगज बैंकर अजय बग्गा ने भी कब है कि अगर ईरान होर्मुज से टोल वसूल सकता है, तो भारत को भी दक्षिण अंडमान में समंदर से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलना चाहिए।

बेतवा सहित तीन बड़ी परियोजनाओं से सिंचाई क्षेत्र में समृद्ध होगा मप्र: सीएम

बोले-नदी जोड़ी से बदेगा जलस्तर बढ़ी आबादी को मिलेगी पानी

विशेष संचाददाता, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केन बेतवा सहित तीन बड़ी परियोजनाओं के चलते जहां प्रदेश के कई जिलों में भूमि जलस्तर में सुधार होगा, तो वहीं वहां की पेयजल व्यवस्था भी पहले से ज्यादा बेहतर होगी। अकेले केन बेतवा परियोजना से 10 जिलों की 41 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की तीन अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाएं किसानों की समृद्धि और प्रदेश की तरक्की का आधार बन रही हैं। किसानों को भरपूर पानी मिलेगा, जिससे वे एक वर्ष में तीन-तीन फसलें ले सकेंगे। उन्होंने कहा, उप्र के साथ केन-बेतवा लिंक परियोजना,



डिजिटल तकनीक से किसान होंगे समृद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार किसानों के जीवन को आसान बनाने डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग कर रही है। डिजिटल किसान डेटा इंटीग्रेशन से किसानों की जमीन, फसल उत्पादन से जुड़ी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो रही है, जिससे योजनाओं का लाभ तेजी से किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। डॉ. यादव ने कहा, वर्ष 2026 को प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीकों, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से किसानों के लिए लाभकारी कृषि का समग्र विकास सुनिश्चित करना है।

राजस्थान के साथ पार्वती-चंबल-कालीसिंध परियोजना और महाराष्ट्र के साथ मेगा-तापी अंडरग्राउंड वॉटर रिचार्ज परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। इनके पूरा होने पर मप्र में कृषि, उद्योग, पेयजल के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होगा। देश की प्रथम अंतर्राज्यीय

नदी जोड़ो परियोजना केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना से दो चरणों में मप्र में 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई क्षमता विकसित की जानी है। 126 एमसीएम जल से 10 जिलों की 41 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी।

ट्रंप का एक फोन और मान गए नेतन्याहू

इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने लेबनान के साथ जल्द सीधी बातचीत की मंजूरी दे दी है। उनका यह बयान तब आया है, जब लेबनान पर इजरायली बमबारी से अमेरिका-ईरान संघर्षविराम कमजोर पड़ता नजर आया है। इस बीच ट्रंप ने भी नेतन्याहू से फोन पर बात की है और लेबनान पर हमले कम करने को कहा। इसके बाद लेबनान को लेकर नेतन्याहू के सुर नरम पड़ते दिख रहे हैं। इस बातचीत में मुख्य जोर हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने तथा पड़ोसी देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने पर होगा। उन्होंने बेरूत को सैन्य-मुक्त क्षेत्र बनाने के लेबनान के प्रधानमंत्री के आह्वान का स्वागत किया। लेबनान की ओर से इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ईरान और अमेरिका, दोनों ने ही युद्धविराम की घोषणा के बाद अपनी-अपनी जीत का दावा किया था। वे अब एक-दूसरे पर दबाव डालते नजर आ रहे हैं।

ईरान से बात मनवाने पाक का किया था यूज

वॉशिंगटन। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ औपचारिक वार्ताएं ही नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे चलने वाली 'शांत कूटनीति' भी बड़े फैसलों को आकार देने में अहम होती है। ऐसा ही ईरान जंग में किया गया। अस्थायी युद्धविराम की कोशिशों में अमेरिका ने पाकिस्तान को अहम बैक-चैनल के तौर पर इस्तेमाल किया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक, वाइट हाउस ने सीधे बातचीत के बजाय इस्लामाबाद के जरिए तेहरान तक बात पहुंचाई।

पूर्व इजराइली आर्मी चीफ का फोन हैक का दावा

ईरान से जुड़े हंदाला हैकर ग्रुप ने दावा किया है कि उसने इजराइली सेना के पूर्व प्रमुख हर्जी हलेवी के फोन और दूसरे डिवाइस हैक किए थे। हैकर ग्रुप का कहना है कि वह कई सालों से चुपचाप उनके सिस्टम में घुसा था। इस दौरान उसने हजारों फोटो और वीडियो इकट्ठा किए। उसे इजराइल की सीक्रेट मीटिंग, सेना के ठिकाने और कई अहम अंदरूनी जानकारी मिलती रहीं। ग्रुप ने कुछ फोटो और वीडियो जारी किए हैं। इनमें हलेवी अलग-अलग सैन्य ठिकानों पर जाते, मीटिंग करते, अधिकारियों से बात करते दिखते हैं। कुछ तस्वीरें उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी हैं, जिनमें परिवार की फोटो, पहचान पत्र जैसी चीजें शामिल हैं। इन लीक में कुछ ऐसी मुलाकातें सामने आई हैं जिनके बारे में पहले सार्वजनिक जानकारी नहीं थी।

कांग्रेस की आज बड़ी बैठक 33% महिला आरक्षण पर बनेगा बड़ा प्लान

नई दिल्ली, जेएनएन। कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को लेकर अपनी रणनीति को धार देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक बुलाई है, जिसमें इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब महिला आरक्षण को लेकर देशभर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में कांग्रेस के शीर्ष नेता शामिल होंगे और महिला आरक्षण बिल पर पार्टी की स्पष्ट और ठोस रणनीति तय की जाएगी। संसद के भीतर, बाहर इस मुद्दे को किस तरह उठाया जाए, इस पर भी विचार-विमर्श होगा, ताकि पार्टी राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर सके। महिला आरक्षण बिल लंबे समय से देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। यह बिल संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान करता है।

प्रदेश में नहीं चलेगी 15 साल पुरानी कमर्शियल बसें: हाईकोर्ट

जागरण, जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस महत्वपूर्ण आदेश को पूर्णतः वैध करार दिया, जिसके तहत 15 साल से अधिक पुरानी कमर्शियल बसें के संचालन पर रोक लगा दी गई थी।

बनाने का अधिकार है। न्यायालय ने गत 27 फरवरी 2026 को सुरक्षित रखा फैसला सुनाया। मप्र सरकार ने 14 नवंबर 2025 को एक आदेश जारी किया था। जिसमें 15 साल की समय सीमा पूरी कर

सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने सबी ठहराते हुए बस आपरेटरों की याचिका की खारिज

चुके व्यावसायिक वाहनों (विशेषकर बसें) को सड़कों से हटाने का निर्देश दिया गया था। प्रदेश में वर्तमान में 899 ऐसी बसें चल रही हैं जो अपनी आयु सीमा पार कर चुकी हैं। बस संचालकों ने तर्क दिया था कि उनके पास वैध फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट मौजूद हैं। सभी याचिकाकर्ताओं के पास वैध स्टेज कैरिज परमिट हैं। परमिट का समय-समय पर नवीनीकरण भी कराया गया है। फिटनेस सर्टिफिकेट और टैक्स भी नियमित रूप से जमा किए गए हैं।

अपनी आयु सीमा पार कर चुकी हैं। बस संचालकों ने तर्क दिया था कि उनके पास वैध फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट मौजूद हैं। सभी याचिकाकर्ताओं के पास वैध स्टेज कैरिज परमिट हैं। परमिट का समय-समय पर नवीनीकरण भी कराया गया है। फिटनेस सर्टिफिकेट और टैक्स भी नियमित रूप से जमा किए गए हैं।

शुभ अक्षय तृतीया / स्मार्ट अक्षय तृतीया /

अक्षय तृतीया
अब बनेगा और भी स्मार्ट।
न्यूनतम बनवाई।
ज्यादा सोना, कम कीमत।

फ्लैट 9%*
बनवाई सोने के गहनों पर
चुनिदा गहनों पर लागू

फ्लैट 99%* छूट
हरी के गहनों में सोने पर
चुनिदा गहनों पर लागू

अपने गहने प्री-बुक कीजिए और पाइए

डबल गोल्ड रेट सुरक्षा*

+ मुफ्त* सोने/चांदी का सिक्का

ऑफर 13 अप्रैल, 2026 तक मान्य

हमारे उत्तम कलेक्शन को देखने के लिए स्कैन करें।
अब www.reliancejewels.com पर भी उपलब्ध

भोपाल : शॉप नं. जी/11, डी बी मॉल, अरेरा हिल्स के सामने, एमपी नगर, फोन : 8815213119 / 9238106118 | इंदौर : सत्यराज बिल्डिंग, मल्हार मॉल के सामने, ए बी रोड, फोन : 9201776394 / 9425974347

NETWORK RJBS-26 MP Hin

संस्थापक ► गुरुदेव गुप्त

संपादकीय

युद्ध विराम : रणनीति में बदलाव का संकेत

तमाम किंतु-परंतु के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा से दुनिया की उस युद्ध से राहत मिली है, जिसने संघर्षरत पक्षों के अलावा पूरी दुनिया के लोगों के जीवन यापन को गहरे तक प्रभावित किया। निस्संदेह इस युद्ध ने पश्चिम एशिया के रणनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदलने के साथ ही वैश्विक कूटनीति पर असर डाला है। एक माह से अधिक समय तक चले इस युद्ध में विनाशकारी हवाई हमलों, हार्भुज जलडमरूमध्य की प्रभावी नाकाबंदी और सभ्यता के विनाश के खतरों के बाद अब एक अस्थायी विराम ने पूरी दुनिया को राहत दी है।

युद्ध भले ही अमेरिका-इराइल और ईरान के बीच लड़ा जा रहा था, लेकिन इसने दुनिया के तमाम देशों, उसके नागरिकों, वैश्विक बाजारों और ऊर्जा पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को गहरे तक प्रभावित किया। उनके लिये अस्थायी युद्ध विराम होना निस्संदेह राहतकारी खबर है। इसके बावजूद हकीकत यह है कि इस नाजुक शांति के पीछे कई चिंताजनक सच्चाइयां छिपी हुई हैं। यह सर्वविदित है कि जिन उद्देश्यों को लेकर अमेरिका-इराइल ने यह युद्ध शुरू किया था, वे कहीं से पूरे होये नजर नहीं आते। वह बात अलग है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार लक्ष्य पूरे होने की दलील देते रहते हैं। वहीं ईरान भी युद्ध विराम की अपनी सफलता के रूप में दर्शा रहा है। दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप इस युद्धविराम को अमेरिकी सैन्य प्रभुत्व के प्रमाण और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को खत्म करने के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान इसे अपनी एक रणनीतिक जीत बताता है। उसकी दलील है कि उसने दुनिया की सुपरपाॅवर अमेरिका व आक्रामक इराइल की सेनाओं के हमलों का अकेले ही मुकाबला किया और वैश्विक तेल आपूर्ति पर अपने प्रभाव को प्रदर्शित किया है। ऐसे में कूटनीति के जानकार आशंका जता रहे हैं कि ये परस्पर विरोधी बयानबाजी स्थायी शांति की दिशा में एक कारगर कदम नहीं, बल्कि महज रणनीति में बदलाव का संकेत है।

मौजूदा परिदृश्य व लगातार संवेदनशील घटनाक्रमों के बीच कहना मुश्किल है कि यह युद्धविराम किसी तार्किक परिणति तक पहुंचेगा। कहा नहीं जा सकता कि युद्धविराम के बावजूद इराइल पड़ोसी देशों पर हमले रोकेगा। वह कह रहा है कि लेबनान पर उसके हमले जारी रहेंगे। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति की ‘पल-पल, क्षण-क्षण’ बदलती बयानबाजी और दूसरी ओर इराइल की आक्रामक रणनीति स्थायी शांति के मार्ग में संदेह के कांटे बोती नजर आती है। ईरान भी कह रहा है कि यदि उस पर इराइल के हमले जारी रहते हैं तो वह सीमाओं से परे संघर्ष का विस्तार करेगा, जो निश्चित ही चिंता की बात है। युद्ध विराम की खबरों के बीच इराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाना और हमले में नागरिकों के घायल होने की खबरों ने दुनिया की चिंता को बढ़ाया है। इराइली प्रधानमंत्री नेतन्याह का यह बयान कि लेबनान में संघर्ष का मोर्चा सक्रिय रहेगा, युद्धविराम की सीमाओं को ही दर्शाता है। अमेरिका-ईरान युद्ध के समांतर संघर्षों को नजरअंदाज करने वाला यह युद्धविराम टिकाऊ होगा, इसमें संदेह व्यक्त किया जा रहा है। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान के प्रमुख मध्यस्थ के रूप में उभरने के बीच युद्धविराम की शर्तों की परस्पर विरोधी व्याख्याएं चिंता बढ़ाने वाली हैं।

आशंका जतायी जा रही है कि युद्ध विराम को लेकर स्पष्टता का अभाव, मामूली उल्लंघन भी समझौते को विफल कर सकते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो यह युद्धविराम संघर्षरत पक्षों के इरादे की परीक्षा भी है। निस्संदेह, मौजूदा स्थिति वार्ताओं के लिये एक सीमित अवसर प्रदान करती है। यह भी स्पष्ट करती है कि उपलब्धियां कितनी जल्दी खोई जा सकती हैं। आशंका जतायी जा रही है कि यदि इस्लामाबाद में प्रस्तावित वार्ताएं दोनों के पक्षों के बीच जारी मतभेदों की खोई को पाटने में विफल रहती हैं तो जल्द ही क्षेत्र में युद्ध के बादल फिर से मंडरा सकते हैं।

प्रसंगवश

रेत के अवैध खनन पर रोक लगाना जरूरी

मध्य भारत में स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य तीन राज्यों में फैले एक क्षेत्र में जलीय परिवेश (लोटिक इकोसिस्टम) की रक्षा करता है। इसका अस्तित्व गंभीर रूप से लुप्तप्राय भड़ियाल, लाल मुकुट वाले कछुए और लुप्तप्राय गंगा नदी के डेल्टिकल के लिए महत्वपूर्ण है। ये तीनों प्रजातियां जीवित रहने के लिए रेत पर निर्भर करती हैं। खासकर नदी के रेतिले टीलों और रेतिले किनारों पर। फिर भी, संगठित अपराध और राज्य की निष्क्रियता उसी रेत को चुरा रही है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय रेत खनन माफिया को ‘आधुनिक डाकू’ कहा है।

उत्तर भारत में निर्माण कार्य में आई तेजी के दौरान रेत की मांग को पूरा करने के लिए इस माफिया का उदय हुआ। अदालत एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) द्वारा इस गतिविधि पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद, वे तीन राज्यों – राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश – के बीच अधिकार क्षेत्र की उलझनों का फायदा उठाने में कामयाब रहे हैं। राज्य सरकारों ने भी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दूसरों पर डालकर इस साजिश में एक तरह से सहयोग किया है। साल 2017 से 2024 के बीच, अवैध रूप से खनन की गई रेत से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों ने जहां वन रक्षकों और पुलिस अधिकारियों को कुचला, वहीं खननकर्ताओं ने छापेमारी के दौरान पुलिस पर गोलियां भी चलाईं। पुलिस के मुताबिक खननकर्ताओं ने मोबाइल ऐप एवं जीपीएस का उपयोग करके गश्ती वाहनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए स्थानीय ग्रामीणों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। खबरों से पता चलता है कि 2023 से ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में खनन गिरोह और-स्वचालित हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अक्सर स्थानीय वन विभाग के अमले पर भारी पड़ रहे हैं।

खून-खराबे को रोकने में विफल रहने से हताश होकर, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने इस अभ्यारण्य के भीतर कुछ जिलों में रेत खनन को वैध बनाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश ने दो जिलों में सीमित खनन के लिए प्रस्ताव पेश किए थे, लेकिन एनजीटी के विरोध के चलते उसकी योजनाएं रुक गईं और राज्य ने बाद में उन प्रस्तावों को वापस ले लिया। राजस्थान ने इसी साल मार्च में इसी किस्म का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। चंबल की घाटियां में पारंपरिक तरीके से खेती करना मुश्किल है। इसकी वजह से कई युवा अपनी आजीविका के लिए रेत खनन की ओर रुख करने को मजबूर हो जाते हैं। माफिया उन्हें अपने निजी सैनिकों के रूप में भर्ती करता है। नतीजतन, वन अधिकारियों को माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पर ‘जनता की नाराजगी’ का सामना करना पड़ता है। अदालत ने राजस्थान के इस कदम का स्वतः संज्ञान लिया और न्यायभूमि संदीप मेहता ने पिछले हफ्ते राज्य को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और राज्य-विशिष्ट गुंडा अधिनियम की ‘याद’ दिलाई। अदालत की निराशा स्वाभाविक है। लेकिन हरित प्रशासन के हालिया समर्याग्रस्त इतिहास, जहां इसने नियामक की भूमिका निभाई है, के महैनजर अदालत द्वारा नियामक को बदलने के बजाय उसे अनुशासित करना मुनासिब है। चंबल के हिंसक इतिहास से यह सबक मिलता है कि सिर्फ ताकत के जोर से उस अर्थव्यवस्था पर ढक्कन नहीं लगाया जा सकता जो शिकायतों पर पनपती है। व्यापक स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई से स्थानीय असंतोष और गहराएणा और उसी सामाजिक आवरण को मजबूत करेगा जो इन गिरोहों को टिकाए रखता है। स्थायी बदलाव सिर्फ वैध आजीविका को बहाल करने और विश्वसनीय एवं निष्पक्ष प्रवर्तन से ही आएगा।



युद्ध और नीति

रणनीति का मतलब अंतहीन संघर्ष नहीं

एस एस मेहता
रिट। लेफ्टिनेंट जनरल

आजकल युद्ध खत्म नहीं होते, खिंचते जाते हैं, अपना स्वरूप बदल रहे हैं और खुद को जायज ठहराते हैं। यह रणनीति नहीं है। यह रणनीतिक रूपरेखा की असफलता है। मैंने युद्धों को खत्म होते देखा,और उन्हें खत्म होने से इनकार करते भी। सेना में, हमें युद्ध शुरू करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। हम आरंभिक व्यूह रचना, जौरदार हमले, शत्रु का घेरा तोड़ने व इच्छाशक्ति कुचलने का अध्ययन करते हैं। युद्ध का विस्तार करना समझते हैं, शत्रु का घेरा तोड़ने अथवा शांत अनुशासन है जो कभी रणनीति को परिभाषित करता था, लेकिन अब धीरे-धीरे धुंधला रहा है। वह है, रुकने की कला।

दरअसल, जिन संघर्षों का अंत बढ़िया हुआ, उनकी संरचना सीधी-सादी थी। दुश्मन को पूरी तरह मिटाना नहीं, बल्कि उद्देश्य में स्पष्टता रखना। तब, किसी में इतनी हिम्मत होती थी कि वह फैसला कर सके कि मिशन पूरा हो गया है। इसलिए नहीं कि दुश्मन का खान्ता हो गया, बल्कि इसलिए कि काम पूरा हो गया था। बल का इस्तेमाल हुआ। तयशुदा सीमा तक पहुंचे। फिर आया सबसे मुश्किल आदेश : रुको। घर वापसी करो। आज, वह माद्दा गायब है। कोई फैसला नहीं करता। संघर्ष खिंचते रहते हैं। बिना किसी तय अंत वाला युद्ध कोई अभियान नहीं होता। यह तो जान-माल की हानि के साथ भटकाने है।

भारत का 'गोल्ड स्टैंडर्ड' (सर्वोच्च मानक) : हमें किसी मानक की तलाश करने की जरूरत नहीं है। साल 1971 में, भारत ने आधुनिक इतिहास के सबसे निर्णायक अभियानों में से एक को अंजाम दिया। यह सिर्फ जीत नहीं थी। यह उसके बाद बरते गए संभम का उदाहरण था। हम वहां रुके नहीं रहे। हमने अपनी जीत को कब्जे में नहीं बदला। हमें भान था कि 'पूरा हुआ काम' कैसे दिखता है।1988 में मालदीव में, हमने दखल दिया, व्यवस्था बहाल की और वापसी कर ली। पीछे कुछ बाकी नहीं छोड़ा। कोई अन्य एजेंडा नहीं। प्रभाव अधिकतम, दखल न्यूनतम। यहां तक कि श्रीलंका में भी, जहां पर हालात बहुत पेचीदा थे, हमने तब पीछे हटने का अनुशासन दिखाया, जब हमें लगा कि अब वहां से कुछ खास हासिल नहीं होने वाला। भारत का संयम सिर्फ इसमें नहीं था कि उसने क्या किया, बल्कि इस बात में भी था कि उसने किन चीजों पर हमला न करना चुना। बुनियादी ढांचे को कभी भी निशाना नहीं बनाया। इसी आधारभूत ढांचे पर किसी भी समाज का जीवन टिका होता है। इसे तबाह करने का मतलब है, उन्हीं लोगों को सज़ा देना जिनके नाम पर अक्सर युद्धों को सही ठहराया जाता है। इसी

ट्रांसजेंडर कानून

संशोधन से मर गयी ट्रांसजेंडर कानून की आत्मा

योगेन्द्र यादव
चलिए, ट्रांसजेंडर कानून में हुए संशोधन की बात ‘कामसूत्र’ से शुरू करते हैं. संस्कृत साहित्य के इस कालजयी ग्रंथ में स्त्री और पुरुष के अतिरिचत एक तृतीया प्रकृति का जिक्र किया गया है. वात्स्यायन के अनुसार, यह मामला ‘प्रकृति’, यानी स्वभाव या मनोवृत्ति का है, शरीर की लैंगिक बनावट का नहीं. इस तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनका शरीर तो पुरुष जैसा है, पर मन और हाव-भाव या तो स्त्रीरूपिणी है, या कम से कम वह नहीं है जिसे समाज पुरुष के रूप में पहचानता है. या वह जो जन्म से लड़की मानी गयी, पर जिनका आचार-व्यवहार स्त्री के लिए बनाये खांचे में फिट नहीं बैठता. वात्स्यायन इस तीसरी प्रकृति को किसी विकार की तरह देखने की बजाय, बस एक अन्य श्रेणी की तरह दर्ज करते हैं. ट्रांसजेंडर शब्द भले ही नया हो, पर पश्चिमी संस्कृति से संपर्क से सैकड़ों वर्ष पहले हमारे यहां इस बात की कमोबेरी सहज स्वीकारोक्ति थी कि कुछ लोग तन से और कुछ लोग मन से पुरुष बनाम स्त्री के दो डब्बों में कैद नहीं हो सकते. हमारी भाषाओं और परंपराओं में अनगिनत कथाएं और मिसाल यह साबित करते हैं कि लैंगिक विविधता का विचार हमारे यहां कहीं बाहर से नहीं आया. दरअसल, औपनिवेशिक संस्कृति के वर्चस्व के चलते हमने इस लैंगिक विविधता के प्रति शर्म महसूस करनी शुरू की और अंग्रेजों की नकल करते हुए ऐसे सामाजिक आदर्श बनाये, जिनमें तीसरी प्रकृति के लिए जगह नहीं थी. यही नहीं, ब्रिटेन की तरह हमारे यहां भी ऐसे कानून बनाये गये, जो स्त्री-पुरुष के एकरूपी संबंध से हटकर हर संबंध और हर आचार-व्यवहार को गैरकानूनी बना देता था.

जीवन दर्शन

हर मनुष्य अपने आप में अलग होता है, जैसे एक विशाल समंदर में कई छोटे-छोटे द्वीप होते हैं। हम सब अलग जरूर हैं, पर हमारे बीच कुछ ऐसी बातें होती हैं, जो हमें एक-दूसरे से जोड़ती हैं। हम साथ रहते हैं, एक-दूसरे के करीब होते हैं, एक-दूसरे के जीवन में दखल देते हैं, प्रभाव डालते हैं और प्रतिक्रियाएं भी देते हैं, फिर भी हर क्षण, हर परिस्थिति में हम अक्सर खुद को अकेला ही पाते हैं। यह अकेलापन कोई संयोग नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का मूल स्वभाव है। जब दो करीबी मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, तब वे एक-दूसरे का हाथ थाम सकते हैं, पर अंतिम क्षणों की पीड़ा केवल उनकी ही होती है। कोई दूसरा उनके उस अनुभव को महसूस नहीं कर सकता है। प्रेमी भी जब एक-दूसरे को गले लगाते हैं, तो वे अपनी-अपनी सीमित खुशियों और अनुभूतियों को एक करने की पूरी कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि उनका आनंद एक हो जाए, उनका अस्तित्व एक हो जाए, लेकिन यह प्रयास अंततः असफल ही रहता है। इसकी वजह यह है कि हर आत्मा अपनी ही अनुभूति के घेरे में बंधी होती है। कोई भी चेतन आत्मा, चाहे वह कितनी ही संवेदनशील क्यों न हो, अपने सुख और दुख को अंततः अकेले ही जीती है। हमारी

युद्ध से संयम की अनुपस्थिति,रणनीतिक रूपरेखा की असफलता

संशोधन से मर गयी ट्रांसजेंडर कानून की आत्मा



अनुशासन ने हमारी वैधता को बनाए रखा। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर गौर कीजिए। सटीक। तय परिधि में। उद्देश्यपूर्ण। लक्ष्य हासिल। काम पूरा। और फिर रुक जाना। हरेक मामले में, परिणामों ने साधनों को परिभाषित किया। लेकिन अब साधन खुद मकसद बनने का जोखिम उठा रहे हैं। सिद्धांत के रूप में भटकाव : हम इसे ‘हाइब्रिड वॉर’, ग्रे जोन या सोच-समझकर पैदा की गई अस्पष्टता कहते हैं। धरातल पर यह सरल दिखता है। सिद्धांत के आवरण में भटकाव। पश्चिम एशिया में, उद्देश्य बदलते रहते हैं जबकि युद्ध जारी है। कोई दिन निर्णायक जीत मिलने का अहसास करवाता है। अगले रोज लगता है लड़ाई अब लंबी खिंचेगी। बातचीत, विराम और तनाव इस कदर गडमड हो जाते हैं कि शब्दों का अर्थ ही समाप्त हो जाए। आमजन पर असर की हकीकत : रणनीति यह भूल जाती है कि इस भटकाव की कीमत कौन चुकाएगा। रणनीतिकार मैदान ए जग की बातें करता है। नागरिक इसकी अवधि की कीमत चुकाता है। चाय की दुकान पर बैठा व्यक्ति सिद्धांत नहीं पढ़ा होता। वह तो बाधित हुई आपूर्ति शृंखलाओं से बढ़ती कीमतों का दर्श झेलता है, जो कभी स्थिर नहीं होतीं क्योंकि युद्ध अंतहीन हो चले हैं। वे अपने परिवारों को युद्धक्षेत्रों में फंसा हुआ पाता है जहां से निकलने की कोई राह नहीं। जब युद्ध का कोई निश्चित समय होता है, तो समाज संगठित होता है और उबरता है। जब नहीं तो होता, तो अर्थव्यवस्था और भावनाएं उसी के अनुरूप आकार लेने लगती हैं।

क्षमता का विरोधाभास : संघर्ष समाप्त करने के लिए हमारे पास पहले से कहीं अधिक संसाधन हैं, फिर भी हम उन्हें समाप्त करने में असमर्थ हैं। ड्रोन, साइबर ऑपरेशन और सटीक हमले घोरित युद्ध से इतर दबाव डालने का जरिया बन गए हैं। हम अनिश्चित काल तक न तो शांति और न ही युद्ध की स्थिति बनाए रख सकते हैं। यह एक तरह का जाल है। क्षमता ने निर्णय लेने की शक्ति का स्थान ले लिया है। युद्ध रोकने को जवाबदेही की आवश्यकता पड़ती है। बताने की जरूरत पड़ती है कि क्या पाया और क्या खोया। इसके लिए जिम्मेवारी लेने की जरूरत होती है। किसी नतीजे



सामाजिक बंदिशों और कानूनी बेड़ियों की इस मिलावट ने न जाने कितने खूबसूरत रिश्तों को पाप में बदल दिया, न जाने कितने अरमानों का गला घोट दिया. सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के एक निर्णय से इस ऐतिहासिक अन्याय पर रोक लगायी. ‘राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (नालसा) बनाम भारत सरकार’ नामक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी प्रकृति को कानूनी मान्यता दे दी. इसमें केवल उभयलिंगी (जिनके शरीर में नर और मादा दोनों के लक्षण हों) और हिजड़ा, किन्नर, अरावन्दी, जोगता ही शामिल नहीं थे. बल्कि वे सब, जो इसमें शामिल होना चाहें. जो अपने आपको न पुरुष समझते हैं, न स्त्री. न्यायालय ने सरकार को हिदायत दी कि वह इस तीसरी प्रकृति को मान्यता दे, इनके विरुद्ध होने वाले भेदभाव पर पाबंदी लगाये और इस वर्ग की बेहतरी के लिए भी इंतजाम करे. अंततः, पांच वर्ष बाद संसद ने इस आशय का कानून बनाया. ट्रांसजेंडर व्यक्ति

जीवन दर्शन हम एक-दूसरे से जुड़े भी हैं और अकेले भी



संवेदनाएं, भावनाएं, गहरी समझ, और कल्पनाएं, ये सब हमारे भीतर की निजी दुनिया का हिस्सा हैं। हम उन्हें शब्दों में ढालकर दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन शब्द केवल प्रतीक होते हैं, वे अनुभव को पूरी तरह से जाहिर नहीं कर पाते। दरअसल, हम अपने अनुभवों के बारे में जानकारी साझा तो कर सकते हैं, पर उस अनुभव की गहराई, उसकी सच्ची अनुभूति, कभी भी पूरी तरह किसी और तक नहीं पहुंचती है।

जब हम किसी और के दर्द या खुशी को समझने की कोशिश करते हैं, खुद को उसकी जगह रखकर

की घोषणा करने के मुकाबले में यह कह देना आसान है कि परिस्थिति स्वरूप बदल रही है।

बल का मापन : बल प्रयोग स्पष्टता और उद्देश्य के साथ किया जाए। लेकिन इसकी वैधता विवेक पर आधारित है। यदि एक थप्पड़ ही काफी है, तो लाठी क्यों? यदि उद्देश्य सुधारना है, तो एक व्यक्ति की गलती के लिए पूरे वर्ग को दंड क्यों? बुनियादी ढांचा युद्धक्षेत्र नहीं होता। यह समाज की जीवनधारा होता है। इस पर चोट करने से आप युद्ध को आकार नहीं दे रहे, बल्कि भविष्य को सजा दे रहे हैं। संतुलित प्रतिक्रिया व्यवहार सुधारती है। अंधाधुंध प्रतिक्रिया पीढ़ियों को घाव देता है जो बार-बार लौट आते हैं।

मानवता बतौर वैश्विक संसाधन : कोविड-19, जलवायु परिवर्तन और युद्धों ने एक सरल सत्य उजागर किया। किसी भी संकट का असर स्थानीय नहीं रह सकता। एक क्षेत्र में हो रहा युद्ध महाद्वीपों भर में भोजन, ईंधन, व्यापार और भरोसे को बाधित कर देता है। मानवता अब परम वैश्विक साझा संसाधन है। युद्ध से पहले ही युद्ध जीता जाना चाहिए। और यदि यह संभव न हो, तब विनाश करने की रणनीति बनाएं।

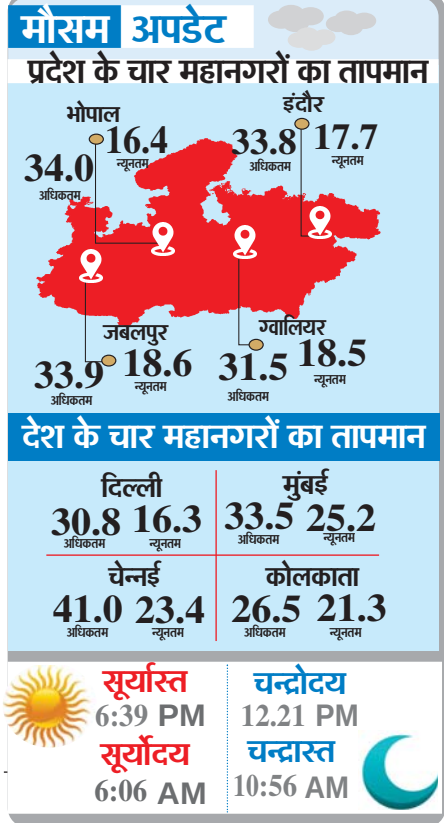
कानून जो हमने कभी सुधारें नहीं : युद्ध कभी भी कानूनविहीन नहीं रहा। इसकी हमेशा सीमाएं रही हैं। जिनवा सम्मेलनों ने आधाररेखा स्थापित की –घायलों की रक्षा। युद्धबंदियों को बचाना, नागरिकों को अभयदान। नागरिक अब रणक्षेत्र से अधिक दूर नहीं रहे। नागरिक परिसरों पर हमला न किया जाए। जीवन-निर्वाह के लिए भोजन, पानी और आवश्यक बुनियादी ढांचे जैसी प्रणालियों को निशाना न बनाया जाए। लेकिन युद्धक्षेत्र कानून से अधिक तेजी से बदल रहा है। आज बिजली गिड पर हमला शहरों को ठप कर देता है। अर्थव्यवस्थाएं डेटा नेटवर्क पर निर्भर हैं। आपूर्ति शृंखला की सततता पर राष्ट्र टिके हैं। इन प्रणालियों का महत्व कम नहीं। वे अपने आप में समाज हैं। और फिर भी, उन्हें निशाना समझा जा रहा। हमें नए सिद्धांतों की जरूरत नहीं, मौजूदा सिद्धांतों को उन युद्धों में लागू करने के लिए अनुशासन की जरूरत है, जो जारी हैं। हमारा न्यूनतम दायित्व : सदियों से, सुन त्चु से लेकर चाणक्य, मैक्वावलली और क्लॉजविट्ज़ तक – रणनीति का मतलब कभी भी अंतहीन संघर्ष नहीं रहा। यह उद्देश्य-क्रियान्वयन-समाप्ति युक्त रणनीति रही है। संयम कमजोरी नहीं, नियंत्रण है। युद्ध की शुरुआत भले रणनीति से हो, लेकिन अंत अनुशासनागत ही होना चाहिए। यदि हम यह तय नहीं कर पाए कि युद्धों का अंत कैसे हो, तो हमें विरासत में अंतहीन संघर्ष मिलेंगे।

भोपाल 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार
वैशाख कृष्ण पक्ष 8 संवत 2083

06

बधाई हो, कट हुआ है...

पीए सिद्धार्थ
झुन्नु लाल जी अपनी सीट पर बैठे-बैठे एक हथेली में एक चुटकी तंबाकू में थोड़ा सा बुझा चूना मिलाने के बाद उसे अंगूठे से अच्छी तरह रगड़ने के बाद निचले होंठ में दबाते हुए संता सिंह से बोले, ‘बधाई हो! सुना है आपको कट हुआ है।’ संता सिंह अपनी ऐनक को एक ओर रखते हुए बोले, ‘हां बड़े बाबू, आपको भी बधाई हो कि आप भी प्रदेश को मुफ्लिसी के जाल से बाहर निकालने में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करवाने जा रहे हैं। पर आप ‘कट हुआ’ तो ऐसे बोल रहे हैं मानो किसी के यहां बेटा हुआ हो। झुन्नु लाल जी खीखी...हीही...करते हुए हंसकर बोले, ‘यार! सच कहूं तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। इसे कहते हैं आगे-आगे दौड़ और पीछे-पीछे छोड़। सरकार को यह कदम तो मेरे घर पर बिल्कुल ठीक बैठता है। श्रीमती हर महीने के शुरु में शोर मचाती हैं कि बचत करनी है। कभी दूध में कट, कभी सब्जी में, कभी लोकल मिल का सुपर फाइन आटा। ग्राोसरी स्टोर में घंटों लगाकर एक-एक सामान खरीदते हुए उनके पांवों का विश्लेषण करती हैं। फिर महीने आखिर में उन्हें यकायक याद आता है कि इस महीने कोई सूट, साड़ी, स्वेटर या जूता नहीं लिया और जो थोड़ा-बहुत बचाया होता है, उसे एक बार में खर्च कर आती हैं। फिर अगले महीने का डेफिसिट शुरू। सरकारें भी तो यही करती हैं। बचत का शोर करते हुए एकाएक किसी तुगलकी योजना का शुभारंभ कर बचत, वर्तमान और भविष्य तीनों का कबाड़ा कर देती हैं।’ ‘यार, मैं तो कई बार सोचता हूं कि उधार लेकर धी पीने की जरूरत क्या थी, राज्य में रही विभिन्न सरकारों को। अब देखो, बड़े साहिब की गाड़ी दो लाख किलोमीटर भी नहीं चली। पर उनके लिए टोयोटा की इनोवा एसक्रॉस आ रही है। घर में साहिब ने बीस साल पुरानी मारुति एस्टीमर खरी है। हर महीने करोड़ों रुपए गाडियों, बंगलों और फर्नीचर पर खर्च किए जा रहे हैं। सरकार की तो शान ही निराली है।’ झुन्नु जी सोचते हुए बोले। संता सिंह गहरी सोच में उतरते हुए बोले, ‘आप सही फरमा रहे हैं। कुछ साल पहले सरकारों ने विश्व बैंक से उधार लेकर पर्यटन की जो ऊटपटांग योजनाएं शुरु की थीं, उनके बारे में अब सोच कर ही हंसी आती है। सिमिट्री टूरिज्म, निर्जन जगहों पर पार्क, रेस्तरां, होटल, चौराहों का सौंदर्यीकरण और न जाने क्या-क्या। रही बात दूध, गेहूं, हल्दी पर समर्थन मूल्य की, तो बाजार में अच्छा दूध पहले ही साठ से अस्सी रुपए किलो मिल रहा है, हल्दी चार सौ और आटा साठ रुपए किलो। आपको लगता है कि इस कटौती से छह महीने में सरकार की वित्तीय हालत अच्छी हो जाएगी और हमारी तनखाह से कटौती बंद हो जाएगी।’ झुन्नु जी हंस्टे हुए बोले, ‘शी...। सुबह-सुबह मजाक करना अच्छी बात नहीं। चलो, अब कुछ काम कर लेते हैं।’



भोपाल, खेप्र। राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने गुजरात की प्रदेश के पहले पिक स्पोर्ट्स शोरूम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं एवं छात्राओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने और उन्हें खेल सामग्री की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मंत्री गौर ने अपने ऑटोग्राफ वाले बैट प्रदान की महिला खिलाड़ियों का सम्मान किया। सिरता कोहली ने कहा कि उनका उद्देश्य महिलाओं और छात्राओं को एक स्थान पर गुणवत्तापूर्ण खेल सामग्री उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें असुविधा का सामना न करना पड़े।

अग्नि सुरक्षा की अनदेखी पर आठ बिल्डिंगें सील

जागरण, इंदौर। बजेश्वरी एनएक्स अग्निकांड के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। शहरभर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच शुरू करते हुए अधिकारियों ने कई बिल्डिंगों में खामियां पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए आठ बिल्डिंगें सील कर दी हैं। गुरुवार को गीताभवन और भवरकुआ क्षेत्र में बिल्डिंगों की जांच की गई। कई संस्थानों में अग्नि सुरक्षा के उपकरण नहीं पाए गए। इसके बाद अफसरों ने उन्हें सील करने की कार्रवाई की।

दैनिक जागरण

भोपाल, 10 अप्रैल 2026

विविध

www.dainikjagranmpcg.com

सोन अभयारण्य में 7 मादा चड़ियालों ने दिए अंडे

जागरण, सीधी। सोन चड़ियाल अभयारण्य में तीन साल से रुके प्रजनन चक्र आरंभकार फिर से शुरू हो गए हैं। अवीक्षक प्रमोद सिंह ने बताया कि हाल ही में सात मादा चड़ियालों ने अंडे दिए हैं। यह अभयारण्य के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। तीन साल पहले अभयारण्य का एकमात्र नर चड़ियाल सोन नदी के बहाव में बहकर बिहार चला गया था। इसके कारण प्रजनन पूरी तरह रुक गया और चड़ियालों की संख्या पर संकट मंडराने लगा था।

12

डा. ऑर्थो ही क्यों खरीदें ?



घुटना दर्द कमर दर्द कंधा दर्द कलाई दर्द

मिलते-जुलते नामों, विज्ञापन से सावधान

Clinically Tested*

*For efficacy and safety.



जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा

8 गुणकारी आयुर्वेदिक तेलों से बना डा. ऑर्थो तेल जोड़ों के दर्द को

जड़ से कम करने में विशेष सहायता करता है। मात्र 8-10ml तेल दिन में सिर्फ एक या दो बार हल्के हाथों से पीड़ित अंग पर मालिश करें।

हर बूंद में असर

Dr. Juneja's
डा. ऑर्थो
Ayurvedic Oil, Capsules, Spray & Ointment



Helpline : 7876977777 • www.drorthoil.com

नल-जल योजना: 2 करोड़ का काम, 12 करोड़ का किया भुगतान

अंजड़ नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष, सीएमओ समेत 9 के खिलाफ एफआईआर

मुख्य संवाददाता, भोपाल। प्रदेश के बड़वानी जिले की अंजड़ नगर परिषद में पेयजल योजना में हुए घोटाले की छानबीन के बाद ईओडब्ल्यू की इंदौर यूनिट ने इस मामले में नगर परिषद के तत्कालीन अध्यक्षों, अधिकारियों और ठेकेदार कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। पड़ताल में उजागर हुआ है कि करीब 12 करोड़ रुपये के इस टेंडर में जमीनी स्तर पर केवल 2 करोड़ का ही काम किया गया, जबकि ठेकेदार को 12 करोड़ का भुगतान कर दिया गया। लगभग 10.20 करोड़ के इस घोटाले में अब शुरुआत 2016 में हुई थी, जब सरकार ने अंजड़ के 2700 घरों में नल कनेक्शन देने के लिए 12 करोड़ 20 लाख रुपये मंजूर किए थे। इस काम का ठेका सोरठिया वेल्वी रत्ना एंड कंपनी को दिया गया था और 18 माह में कंपनी को काम पूरा करना था। काम समय पर पूरा न होने पर बिल की राशि से 10 प्रतिशत कटौती का भी प्रावधान था। इसके बाद भी ठेकेदार को बगैर कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के ही पूरी रकम दे दी गई। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि सरकारी



दस्तावेजों जैसे माप पुस्तिका और कैशबुक में न तो काम का सही विवरण दर्ज है और न ही अधिकारियों व ठेकेदार के हस्ताक्षर हैं। इसके बजाय कागजों में गलत एंट्री कर भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में नगर परिषद की तत्कालीन अध्यक्ष मंजुला राकेश पाटीदार और पुष्पा परमार, तत्कालीन सीएमओ सुरेंद्र सिंह परमार, अमरदास सैनानी और मायाराम सोलंकी को मुख्य आरोपी बनाया है। इनके साथ ही तत्कालीन इंजीनियर दिनेश पटेल, तत्कालीन लेखापाल हुकुमचंद मालवीय, ठेकेदार कंपनी के प्रोपराइटर परेश सोरठिया और ठेकेदार मिनेश मकवाना के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है।

आठ साल चली जांच अब गिरफ्तारी की तैयारी

इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने ठेकेदार से मिलीभगत कर अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया और काम पूरा न होने के बावजूद 10.20 करोड़ का एक्सट्रा पेमेंट कर दिया। ईओडब्ल्यू ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 409, 120बी के तहत धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज बनाना, अमानत में खयानत, साजिश रचने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (सी) व 13(1) ए के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। अब जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। गौरतलब है कि इस मामले की शिकायत लगभग आठ साल पहले की गई थी, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने गहराई से पड़ताल कर पहले सबूत जुटाए और उसके बाद आरोपियों पर शिकंजा कसा।

30 हजार छात्रों के परिणामों पर रोक बरकरार

नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा: परीक्षा परिणाम घोषित करने की अनुमति से हाईकोर्ट का इंकार

जागरण, जबलपुर। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा संबंधित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनस सराफ की युगलपीठ ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के जेएनएम प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने अनुमति देने से इंकार कर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अनसूटेबल कॉलेज के छात्रों को सूटेबल कॉलेज में स्थानांतरित नहीं किया गया है। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद एमपी नर्सिंग काउंसिल को विस्तृत जानकारी पेश करने के निर्देश जारी किये हैं। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की ओर से यह मामला दायर किया गया था। इसमें कहा गया था कि प्रदेश में संचालित अधिकांश नर्सिंग



कॉलेज मापदंडों की पूर्ति किये बिना सिर्फ कागजों में संचालित हो रहे हैं। अधिकांश नर्सिंग कॉलेज के भवन तक नहीं हैं। एक कमरे में संचालित कॉलेज में लैब, लाइब्रेरी से संचालित हो रहे हैं। निर्धारित मापदंड की पूर्ति नहीं करने वाले कॉलेज को मान्यता प्रदान की गयी है। हाईकोर्ट ने प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई

ने सूटेबल, अनसूटेबल तथा आंशिक कमी वाले कॉलेज की सूची हाईकोर्ट में पेश की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अनसूटेबल कॉलेज के छात्रों को सूटेबल कॉलेज में स्थानांतरित करने के आदेश जारी किये थे। याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान एमपी नर्सिंग काउंसिल की ओर से शैक्षणिक सत्र 2022-23 के जेएनएम प्रथम वर्ष के लगभग 30 हजार छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने अनुमति प्रदान करने हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया था। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि छात्रों को सूटेबल कॉलेज में स्थानांतरित नहीं किया गया है। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किये। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आलोक बागरेचा ने पैरवी की।

सौ फीसदी महिला आरक्षण मामले में जवाब तलब

जागरण, जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर के पद सी फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षित करने के मामले को गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले में मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में हो रही नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती में पुरुष उम्मीदवारों को पूरी तरह बाहर रखने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता विनोद सनोदिया और एक अन्य उम्मीदवार द्वारा याचिका में 2 अप्रैल 2026 को जारी भर्ती विज्ञापन और विभाग के भर्ती नियम के किए गए संशोधनों को असंवैधानिक बताया था। याचिकाकर्ताओं

ने तर्क दिया है कि विज्ञापन में नर्सिंग ऑफिसर के सभी 1,256 पद केवल महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। यह मप्र सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम 1997 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि पुरुष उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत प्राप्त समानता के मौलिक अधिकारों का हनन है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार एक संस्थानों में, एक ही पाठ्यक्रम और परीक्षा के माध्यम से नर्सिंग की प्राप्त करते हैं। इसके बावजूद केवल लिंग के आधार पर उन्हें सार्वजनिक रोजगार से वंचित करना अतार्किक और भेदभावपूर्ण है।



11 अप्रैल 2026

कर्वधा

अप्राकृतिक रिश्तों के शोकीन मास्टर को छात्र ने उतारा मौत के घाट

बुस्हानपुर

एकतरफा इश्क में फर्नीचर शोरूम संचालक ने की अपनी सेल्सगर्ल की हत्या

झाबुआ

पति की हत्या कर शराब पीकर रिश्तेदार की शादी में जाकर नाचने लगी नाबालिग बीवी एवं अन्य रोचक कहानियां

LOVED IN
100
COUNTRIES

N160

धाकड़ डेरिंग

अब सिर्फ ₹1 25 500/-
₹120 300/-*

BAJAJ

THE WORLD'S FAVOURITE INDIAN

pulsar

DEFINITELY DARING

16 PS पावर / ABS ड्युअल चैनल ABS / LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प / ब्ल्यूथ कनेक्टिविटी

₹7 500/- तक के अतिरिक्त ऑफ़र्स Flipkart amazon.in पर उपलब्ध हैं.

10 YEAR WARRANTY

BAJAJ SECURE
• AMC • ROAD SIDE ASSISTANCE

72198 21111

AUTO CREDIT

SHRIRAM Finance

DFC FIRST

L&T Finance

TATA CAPITAL
Two Wheeler Loans

*नियम और शर्तें लागू. फ़ायनान्स उपलब्ध है फ़ायनान्सर के अपने स्व-निर्णय पर. पल्सर N160 USD सिंगल सीट वैरिएंट पर दिए गए ई-कॉम ऑफ़र्स, संबंधित ई-कॉम पार्टनर की शर्तों के अधीन हैं. ई-कॉम ऑफ़र्स हर पार्टनर के अनुसार परिवर्तित हो सकते हैं. स्टैंड्स, एक्सपर्ट्स द्वारा प्रोफेशनल सुपरविजन के तहत, आम जनता या आम रास्तों से हट कर नियंत्रित और बंद सीमित वातावरण में किए गए हैं. कृपया इन स्टैंड्स की नकल करने का प्रयास न करें और हर समय ट्रैफिक तथा सुरक्षा नियमों का पालन करें.

मुद्रक एवं प्रकाशक राजीव मोहन गुप्त द्वारा जागरण पब्लिकेशनस प्रा. लि. हेतु 'दैनिक जागरण प्रेस' 33, जागरण भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जेन-1, एम.पी. नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश -462011 (म.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। आर.एन.आई. नं. 1573/57, पंजीयन संख्या 7 म.प्र., संस्थापक : स्व. गुरुदेव गुप्त, संपादक : राजीव मोहन गुप्त, स्थानीय संपादक : हरिमोहन गुप्त फोन : कार्या. : 0755-6723200 E-mail : modemdj@gmail.com।